Canalisation of Imports of Polyester Filament Yarn

1085. SHRI RAM NARESH KUSHAWAHA;
SHRI SHARAD YADAV:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to canalise the imports of polyester filament yarn (PFY) instead of allowing its imports under open general licence; and

(b) if so, what are the reasons therefor stating the likely impact of the decision on the country's textile industry as a whole?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI); (a) No decision has been taken to canalise the imports of Polyester Filament Yam.

(b) Does not arise.

केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा रेशम की किस्मों का विकास

1086. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जून, 1987 के "इकनामिक टाइम्स" में "263 क्रोर रुपीज प्लान फार सिल्क" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अध्यक्ष का पद वर्षों से नहीं भरा गया है और टसर या एरी मूंगा क्षेत्रों से किसी व्यक्ति की बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कभी भी नियुक्ति नहीं की गयी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 263 करोड़ रुपए की समस्त धनराशि को केवल मलबरी के विकास पर खर्च किया जा रहा है जिसका उत्पादन मुख्यतः कर्णाटक में किया जाता है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि टसर और एरी मूगा रेशम की किस्मों का मलबरी के समान विकास नहीं किया जा रहा है और वस्तुतः एरी-मूंगा किस्म समाप्त होने की अवस्था में है ; और

(ङ) यदि हां, तो रेशम की टसर और एरी-मूंगा किस्मों के विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० रण कुमार) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अध्यक्ष का पद 1-6-87 को भरा गया है । अध्यक्ष की नियुक्ति देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित रेशम की किस्म के आधार पर नहीं की जाती है । तथापि, बोर्ड में रेशम की विभिन्न किस्मों के उत्पादन में लगे विभिन्न राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है ।

(ग) जी हां । तथापि इस परियोजना के ब्यौरे को, जिसमें उसका राज्यवार निधिकरण भी शामिल है, विश्व बैंक द्वारा उसके प्रारम्भिक क्लीयरेन्स के बाद, अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

(घ) और (ङ) जी नहीं । केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.) ने बिहार में रांची में एक परिपूर्ण टसर अनुसंधान संस्थान स्थापित किया है, जो टसर उद्योग के लिये अपेक्षित अनुसंधान तथा विकास सहायता प्रदान करता है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मूंगा और टसर तथा एरी के लिये तथा उत्तरी एवं उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में ओक टसर के लिये क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र भी स्थापित किये हैं । इसके अतिरिक्त, आठ राज्यों में टसर उद्योग के विकास के लिये 1981-82 से 1985-86 तक सी.एस.बी. द्वारा 10.50 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से एक अन्तर-राज्य टसर परियोजना कार्यान्वित की गई थी । इस परियोजना से दूसरे चरण को भी 2